

राष्ट्र एवं राज्य के प्रगति पथ पर...

# समय



# दर्शन

निष्पक्ष निर्भीक खबरों के साथ

संस्थापक : स्व. श्रीमती निलिमा खड़तकर

दुर्ग, मंगलवार 16 अप्रैल 2024

www.samaydarshan.in

वर्ष 13, अंक 177 पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रुपये

## सार समाचार

इशाइल-ईरान युद्ध की आहट  
से सहमा बाजार, सेंसेक्स  
800 अंक टूटा, 7.5 लाख  
करोड़ का लगा चुना

**नई दिल्ली।** इशाइल और ईरान के बीच तनाती की स्थिति का शेरब बाजार के खास नुकसान उठाना पड़ा है। पश्चिमी एशिया में तनाती ये येर बाजार में सोमवार को बड़ी गिरावट दिखी। लगातार दूसरे दिन बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 845.12 (1.13%) अंकों को गिरावट के साथ 73,399.78 के स्तर पर बंद हुआ। तीव्री दूसरी ओर, निफ्टी 246.91 (1.10%) अंक टूटकर 22,272.50 के स्तर पर बंद हुआ। सोमवार के कारोबारी सत्र के दौरान एनबीसीसी और विप्री के शेरबों में पांच-पांच प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। 15 अप्रैल के कारोबारी सत्र के दौरान बाजार पर कमज़ोर वैश्विक संकेतों का नकारात्मक असर पड़ा। पश्चिमी एशिया में लगातार बढ़ रहे गतिशील कारण ग्लोबल मार्केट में निवेशकों में सतर्कता बरती बाजार का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा। सोमवार को बाजार की चौथीपक्ष बिकावाली में बैंकिंग, आईटी और मीडिया सेक्टर के शेरब सबसे आगे रहे।

**सलमान खान के घर पर**  
**पर्यारिंग का अंतीत से**  
**जुड़ा कनेक्शन**

मुंबई। हिंदी सिनेमा में दिग्गजों के झांगड़े निपटने में सबसे अहम रसूख रखने वाले अधिनेता सलमान खान को डाकर कनाडा से संचालित अंडरवर्ल्ड परिषेव क्या सेंद्रश देना चाहता है? मुंबई पुलिस इस बात की तपाती बदल संजीदगी से कर रही है। सलमान खान के निकटवर्ती सूच बताते हैं कि इस बारे में सलमान खान से भी लंबी बातचीत पुलिस ने की है। पुलिस जाना चाहती है कि काले हिंदू के मामले से गुस्साए बिश्नोई समाज का ही ये पूरा मामला है।

## चुनाव आयोग ने 44 दिन में 4658.13 करोड़ किए जब्त

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** चुनाव करोड़ के मुफ्त में बांटे जाने वाले आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले 1 सामान, 562.10 करोड़ की कीमती मार्च से 13 अप्रैल तक चेकिंग के दौरान धारुण, 489.31 करोड़ की शराब और देश भर में 4658.13 करोड़ रुपए जब्त 395.39 करोड़ कैश शामिल है। कैश किए हैं। इनमें कैश, सोना-चांदी, शराब, सहित सभी सामानों को मिलाकर हर डूसरे और कीमती सामान शामिल हैं। दिन करोड़ 100 करोड़ रुपए सीज किए लोकसभा चुनाव के 75 साल के जा रहे हैं।

### तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कैश, कर्नाटक में सबसे ज्यादा शराब जब्त

तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 53 करोड़ कैश, तेंगांगा में 49 करोड़, महाराष्ट्र में 40 करोड़, कर्नाटक और राजस्थान में 35-35 करोड़ रुपए से ज्यादा जब्त की गई है। आयोग के मुताबिक, 1 मार्च कैश तरले वर्ष के बाद से देश भर में आदर्श गए हैं। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 124.3 करोड़ की शराब सीज की गई। इसके बाद से जब्त किए गए सामान में 51.7 करोड़, अन्य मुफ्त सामानों को साथ लाने और



राजस्थान में 40.7 करोड़, उत्तर प्रदेश में 35.3 करोड़ और बिहार में 31.5 करोड़ रुपए की शराब जब्त की गई।

### कैश और अन्य सामान को लेकर यहाँ है नियम?

कैश तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 53 करोड़ कैश, तेंगांगा में 49 करोड़, महाराष्ट्र में 40 करोड़, कर्नाटक और राजस्थान में 35-35 करोड़ रुपए से ज्यादा जब्त की गई है। आयोग के मुताबिक, 1 मार्च

16 मार्च को लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद से देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू है। आचार संहिता के बाद से जब्त किए गए सामान में 51.7 करोड़, अन्य मुफ्त सामानों को साथ लाने और

ले जाने को लेकर कई नियम होते हैं, ताकि चुनाव में इनके दुरुपयोग को रोका जाए सके।

चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, एयरपोर्ट पर 10 लाख रुपए तक कैश और 1 किलो तक सोना ले बांट देकर जरिए। 2022-23 में कुल 1300 करोड़ रुपए की पर्फिंग मिली है। इसके बांटने वाले विक्रेता इनके जरिए कांग्रेस को अधिकारी इनकम टैक्स को सूचना देते हैं। वैरिफिकेशन पूरा होने तक कैश या सोना जब्त किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार का नहीं है। इसी तरह किसी वाहन में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिलने पर नेशनल पार्टीजों ने तिव वर्ष 2022-23 में अपनी कुल आय लगभग 3077 करोड़ रुपए किए हैं। इसमें भाजपा होने और सभी डॉक्यूमेंट्स दिखाने पर इनकम टैक्स को मजबूती देता है। भाजपा के पास लगभग 2361 करोड़ थी। 2022-23 में यह बढ़कर 2,361 करोड़ हो गई है।

एसीसीएसन फॉर डेमोक्रेटिक रिफर्मर्स ने बताया कि देश की 6 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिलने पर नेशनल पार्टीजों ने तिव वर्ष 2022-23 में अपनी कुल आय लगभग 3077 करोड़ रुपए किए हैं। इसमें भाजपा का हिस्सा सबसे ज्यादा है। भाजपा के पास लगभग 2361 करोड़ रुपए हैं। किसी पार्टी के उम्मीदवार का डर नहीं है। इसी तरह किसी वाहन के बांटने के लिए देश की 6 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिलने पर नेशनल पार्टीजों ने तिव वर्ष 2022-23 में अपनी कुल आय लगभग 3077 करोड़ रुपए किए हैं। इसमें भाजपा होने और सभी डॉक्यूमेंट्स दिखाने पर इनकम टैक्स को मजबूती देता है। भाजपा के पास लगभग 2361 करोड़ रुपए हैं।

किसी वाहन के उम्मीदवार का डर नहीं है। इसी तरह किसी वाहन के बांटने के लिए देश की 6 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिलने पर नेशनल पार्टीजों ने तिव वर्ष 2022-23 में अपनी कुल आय लगभग 3077 करोड़ रुपए किए हैं। इसमें भाजपा होने और सभी डॉक्यूमेंट्स दिखाने पर इनकम टैक्स को मजबूती देता है। भाजपा के पास लगभग 2361 करोड़ रुपए हैं।

पाप का डर होता है। पीएम ने आगे कहा, मैं आने के बाद से ही एजेंसी लगातार भ्रष्टाचार से लड़ रही है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले ईडी ने सिर्फ 5000 करोड़ की संपत्ति अटेच की थी। क्या तब किसी ने ईडी को कार्रवाई करने से रोका था?

और अधिकारी को किसको इसमें परापरा हो रहा था? जब उन्होंने मेरे गंभीर मंत्री को आदर्श आचार संहिता लागू किया तो उम्मीदवार से नहीं जुड़े। इसमें भाजपा होने और सभी डॉक्यूमेंट्स दिखाने पर इनकम टैक्स को मजबूती देता है। भाजपा के पास लगभग 2361 करोड़ रुपए हैं।

पीएम ने आगे कहा कि देश की संपत्तियाँ अटेच की हैं। 97 फैसली नामाले उन लोगों पर हैं, जो राजनीति से निर्भाव नहीं हैं।

पीएम ने आगे कहा कि देश की संपत्तियाँ अटेच की हैं। 97 फैसली नामाले उन लोगों पर हैं, जो राजनीति से निर्भाव नहीं हैं।

पीएम ने आगे कहा कि एक लाख रुपये की रिकवरी ही एजेंसी के बांटने के लिए देश की संपत्तियाँ अटेच की हैं।

पीएम ने आगे कहा कि एक लाख रुपये की रिकवरी ही एजेंसी के बांटने के लिए देश की संपत्तियाँ अटेच की हैं।

पीएम ने आगे कहा कि एक लाख रुपये की रिकवरी ही एजेंसी के बांटने के लिए देश की संपत्तियाँ अटेच की हैं।

पीएम ने आगे कहा कि एक लाख रुपये की रिकवरी ही एजेंसी के बांटने के लिए देश की संपत्तियाँ अटेच की हैं।

पीएम ने आगे कहा कि एक लाख रुपये की रिकवरी ही एजेंसी के बांटने के लिए देश की संपत्तियाँ अटेच की हैं।

पीएम ने आगे कहा कि एक लाख रुपये की रिकवरी ही एजेंसी के बांटने के लिए देश की संपत्तियाँ अटेच की हैं।

पीएम ने आगे कहा कि एक लाख रुपये की रिकवरी ही एजेंसी के बांटने के लिए देश की संपत्तियाँ अटेच की हैं।

पीएम ने आगे कहा कि एक लाख रुपये की रिकवरी ही एजेंसी के बांटने के लिए देश की संपत्तियाँ अटेच की हैं।

पीएम ने आगे कहा कि एक लाख रुपये की रिकवरी ही एजेंसी के बांटने के लिए देश की संपत्तियाँ अटेच की हैं।

पीएम ने आगे कहा कि एक लाख रुपये की रिकवरी ही एजेंसी के बांटने के लिए देश की संपत्तियाँ अटेच की हैं।

पीएम ने आगे कहा कि एक लाख रुपये की रिकवरी ही एजेंसी के बांटने के लिए देश की संपत्तियाँ अटेच की हैं।

पीएम ने आगे कहा कि एक लाख रुपये की रिकवरी ही एजेंसी के बांटने





# संपादकीय

---

## सीएम ममता का हास्यास्पद तर्क

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) टीम पर हमले और फिर एफआईआर, चोरी और सीनाजोरी का मामला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार की नजर में काई भी केंद्रीय जांच एजेंसी; एनआईए, ईडी या सीबीआई हो, वे सब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की निजी एजेंसियां हैं। इनका इस्तेमाल वे सूबे की सत्ता हासिल करने में करते हैं। लिहाजा, तृणमूल कांग्रेस (तृमूकां) ने निर्वाचन आयोग से मिलकर अनुरोध किया है कि वह भाजपा का चुनावी हित साधने में जांच एजेंसियों के दुरु पयोग रोके। तृमूकां का वहां अपनी बात रखने और उस पर उचित कार्रवाई की आशा का पूरा अधिकार है। पर अंधाखुंबुंध विरोध में ममता इस बात को भूल जाती हैं कि वे केवल तृमूकां की अभियानी नेता भर नहीं हैं। वे मुख्यमंत्री जैसे एक सर्वेधानिक पद पर हैं, जिसका काम प्रदेश के साथ राष्ट्रीय एकता, सम्प्रभुता और अखंडता की रक्षा का भी है। यह तभी हो सकता है कि जब राज्य एवं संघ के कर्तृतत्वों का पालन किया जाए। पहले ईडी और अब एनआईए मामले में ऐसा नहीं हुआ है। एनआईए की टीम 2022 के एक आतंकवादी मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार करने पहुंची थी, उस पर उनके समर्थकों, जिन्हें कांग्रेस नेता अधीर रंजन 'दीदी के गुंडे' कहते हैं, ने हमला कर दिया। मुख्यमंत्री एनआई टीम की कार्रवाई का सपोर्ट करने, उसे पुलिस सुरक्षा देने और हमलावरों की गिरफ्तारी का निर्देश देने के बजाय हास्यास्पद तर्क दे रही हैं। ममता मुख्यमंत्री हैं, उनके अधीन पुलिस समेत राज्य की कई जांच एजेंसियां हैं, जिनकी रात की रेड एक रूटीन-वर्क है। इसी बिना पर एनआईए की रेड का विरोध गैरजिम्मेदाराना है। ममता यह भी जानती हैं कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए गई कोई भी टीम, अगर वह पुलिस से अभिरक्षित नहीं है तो गुस्साए परिजनों के हमले का खुला द्वार होती है। बदसलूकी का उस पर इल्जाम तो मामूली बात है जबकि यह कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने और अफसरों पर हमले का मामला था, जिसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ममता क्या बताएंगी कि संदेशखालि का मामला इतनी ही फूर्ती से क्यों दर्ज नहीं हो सका था? दरअसल, एनआईए प्रकरण से ममता सरकार में संरक्षित आतंकवाद की फिर पोल-पट्टी खुल गई है। ऐसा करके वे चंद बोटों को ही गारंटिड कर सकी हैं। उसी समुदाय के अधिकतर लोगों एवं सूबे का भरोसा हार गई हैं, जिनकी कामना आतंकवाद-मुक्त शांतिपूर्ण-सहअस्तित्व की है।

## केरिवाल की भूमिका

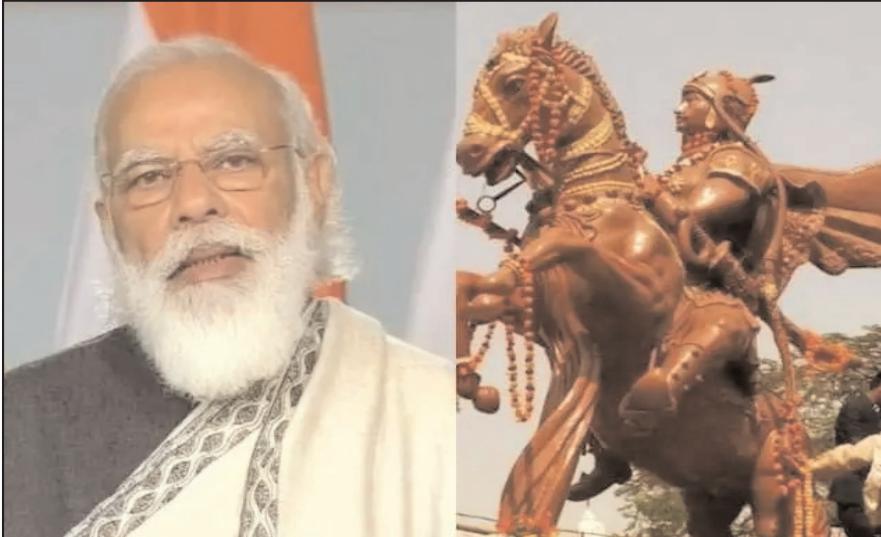
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के जरीवाल की गिरफतारी और रिमांड को 'वैध' और 'न्यायसंगत' करार दिया है। केरजीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) को अदालत ने तब करारा झटका दिया, जब उसने शराब नीति और कथित घोटाले में दोनों की सलिसता भी मानी। अदालत ने प्रवर्तन निवेशलय (ईडी) के साथ्यों और दस्तावेजों के सौजन्य से कहा कि केरजीवाल साजिश में शामिल थे। उन्होंने 'आप' के राष्ट्रीय संघोजक के तौर पर घूस भी मांगी थी। रिश्वत का पैसा गोवा चुनाव में खर्च किया गया। उसकी मरी ट्रेल भी स्पष्ट है। कानून की दृष्टि से मुख्यमंत्री को कोई विशेषाधिकार नहीं है कि उनकी गिरफतारी चुनाव के समय पर न की जाती। ईडी ने जो सामग्री, तथ्य, ई-मेल और व्हाट्सएप चैट के ब्योरे अदालत के सामने रखे हैं, वे सही और पर्याप्त हैं। जांच एजेंसी ने सबूतों के आधार पर गिरफतारी की है। केरजीवाल गवाहों से 'क्रॉस' कर सकते हैं। जस्टिस रामपाल सार्फ़ ने संभिला से एक विवाही नींव ली है।

स्वर्णकाता शमा न गभारता स यह टिप्पणा का ह। असरकारी गवाहों पर उंगली उठाना अदालत और न्यायाधीश पर अक्षेप लगाना है। अदालत का सरोकार संवैधानिक नैतिकता के प्रति है। अदालत पर कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं होता और न ही उसे चुनाव के समय, चुनावी टिकट और चुनावी बॉन्ड से कोई लेना-देना है। सरकारी गवाहों के बयान पीएमएलए और धारा 164 में न्यायाधीश के सामने लिए गए हैं। सरकारी गवाह का प्रावधान सैकड़ों साल पुराना है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि इन प्रावधानों का उपयोग केजरीवाल को फँसाने के लिए किया गया। यह मामला ईडी और केजरीवाल के बीच का है। इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। केजरीवाल ने उच्च न्यायालय में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी, गलत करार दिया था, लेकिन जस्टिस स्वर्णकाता शर्मा ने इन टिप्पणियों के साथ केजरीवाल की अर्जी को खारिज कर दिया। केजरीवाल और 'आप' के सामने अब भी सर्वोच्च अदालत में इस फैसले को चुनौती देने का संवैधानिक विकल्प शेष है, लेकिन उच्च न्यायालय के स्तर पर यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि शाराब नीति बनाने और उसकी आड़ में घूस मांगने के कथित अपराध में केजरीवाल भी संलिप्त थे। बेशक 'आप' के नेता और प्रवक्ता दलीलें देते रहें कि चवत्री भी बरामद नहीं हुई है। केजरीवाल को फँसाना और जेल तक पहुंचाना अभी तक की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है। भाजपा 'आप' को कुचल देना चाहती है, दिल्ली की सरकार गिराने के उसके मंसूबे हैं। 'आप' राजनीतिक स्तर पर कितने भी अभियान चलाए, लेकिन अदालत के सामने ठोस साक्ष्य हैं। उन्हें अदालत ने बुनियादी तौर पर स्वीकार भी किया है। हवाला ऑपरेटर्स के बयान भी मौजूद हैं। जिन्होंने घूस की राशि दी है, उनके बयान, ई-मेल, व्हाट्स एप चैट, बैठकों और मुलाकातों आदि के ब्योरे भी उपलब्ध हैं। केजरीवाल और 'आप' किस-किस को झुटलाने की कोशिश करेंगे। दरअसल केजरीवाल एक चक्रव्यूह में फँस चुके हैं। उनकी कानूनी टीम और अन्य सलाहकारों ने गलत सलाह दी। केजरीवाल को ईडी के 9 समन्स को खारिज नहीं करना चाहिए था। अब जो कानूनी निष्कर्ष सामने हैं, वे उच्च न्यायालय के हैं। किसी के खोखले आरोप नहीं हैं। नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि यदि 'आप' का भ्रष्टाचार भी साबित हो गया और 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक के नाते केजरीवाल का अपराध भी साबित हो गया, तो चुनाव आयोग 'आप' की मान्यता भी रद्द कर सकता है। 'आप' के प्रवक्ताओं को शरत रेट्टी और 60 करोड़ रुपए के चुनावी चंदे और भाजपा की वाशिंग मशीन में धुल कर आरोपितों के पाक-साफहोने सरीखे तर्कों के अलावा कुछ और भी ठोस तर्क देने देंगे।

# प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्र नीति बनाम राजनीति

**राकेश कुमार आर्य -**

31 जनवरी 2024 को देश की राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया और अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया। 5 फ़वरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के बजट अधिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में अपना भाषण दिया। उहोंने अपने भाषण में अपने 10 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इससे पहले देश की राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू सरकार की उपलब्धियों पर अपना भाषण दे चुकी थीं। स्पष्ट है कि इस प्रकार के भाषण को देश का विपक्ष कर्तव्य बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यही कारण रहा कि विपक्ष ने अपनी पंपरागत नीति, रणनीति और राजनीति का परिचय देते हुए बजट भाषण की कटु आलोचना की। लोकतंत्र की ख़बसूरती ही यह होती है कि वह आलोचना का अवसर प्रदान करता है, पर इस ख़बसूरती का भारत का विपक्ष पिछले 10 वर्ष से अनुचित लाभ उठा रहा है। देश का विपक्ष आलोचना के अपने अधिकार को नकारात्मकता में ढालकर प्रस्तुत करता है। इसलिए वह सरकार की अच्छाइयों में वीरी वापरी विवादों से बचा रहा है।



दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के शासनकाल में देश के खजाने को सरकार में बैठे लोगों के साथ मिलकर लूटा जा रहा था। ऐसी अनेक महिलाएं थीं जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ पर वह विधाया पेंशन ले रही थीं। प्रधानमंत्री ने इनकी संख्या 3 करोड़ बताई। यहां पर यह बात भी उल्लेखनीय है कि कशीर में भी ऐसे अनेक अलगाववादी आतंकवादी सोच के लोग रहे जिन्हें कांग्रेस की सरकार करोड़ों रुपया यह सोच कर देती रही कि इससे वह देश की मुख्यधारा में सम्मिलित होकर काम करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। मोदी सरकार ने निसंकोच ऐसे अलगाववादियों को अलगाववादी कहा और उनकी ऐसी सरकारी सुविधाएं समाप्त कर दी गईं। सचमुच मोदी जी का यह एक ऐतिहासिक निर्णय था। उस समय इस निर्णय पर भी विपक्ष के सेकुलर गैंग ने शोर शराबा किया था, पर आज इस पर कोई चर्चा नहीं होती। क्योंकि सबने इस बात को मान लिया है कि मोदी जी के द्वारा उस समय एक ऐसी गलती को मुद्धारा गया था जो देश विरोधियों को प्रोत्साहित करते हुए सरकार के द्वारा की जा रही थी। हम सभी यह भली प्रकार जानते हैं कि आज भारत विश्व की अग्रणी डिजिटल अर्थव्यवस्था है।

मन्त्रियोन्नित विकास के द्वारा मन्त्रियोन्नित दिस्कोरो

किया नहीं गया। यद्यपि भारत का बहुत बड़ा भाग समुद्र से जुड़ा होने के कारण बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका मछली पालन से आजीविका के संबंध जुड़ा हुआ है। मोदी जी ने इन सभी लोगों के कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापन की। पशुओं के स्वास्थ्य और चिकित्सा के प्रति भी सरकार ने गंभीरता और संवेदनशीलता दिखाते हुए पशुओं को 50 करोड़ से अधिक के टीके लगाए। प्रधानमंत्री के अनुसार यह नये आर्थिक साम्राज्य की नई पहचान है। घरेलू महिलाओं को ग्राहिणी के रूप में मान्यता और सम्मान दिलाने की दिशा में भी मोदी सरकार ने विशेष पहल की। भारत में प्राचीन काल से ही महिला को गृहस्वामिनी का सम्मान सूचक संबोधन दिया जाता रहा है। आज इस दिशा में आगे बढ़ते हुए काम किया गया है। जिसके परिणाम स्वरूप देश की अनेक ग्राहणियों के नाम से बिजली के बिल, कनेक्शन आते हैं। घर महिलाओं के नाम हो रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को पहले नौकरी जाने का खतरा रहता था, पर अब 36 सप्ताह की छुट्टी उन्हें मिलती है और इसका वेतन भी उनको यथावत प्राप्त होता रहता है। इससे महिलाओं को विशेष सम्मान प्राप्त हो रहा है।

सुनान्याजत वकास के लिए सुनान्याजत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है और यह बात इस डिजिटल अर्थव्यवस्था में स्पष्ट दिखाई देती है। इस डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते सस्ता मोबाइल मिलना आरंभ हुआ। इससे देश के युवाओं का दृष्टिकोण बदला। देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए। देश के इतिहास में हजारों वर्ष से मछुआरे अपनी आजीविका के लिए मछली पालन को एक उद्योग के रूप में अपनाते चले आए हैं। परंतु इनके लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं था। आजादी के बाद

चलते हैं। आजीविका के ये साधन वास्तव में हमारी वर्ण व्यवस्था के प्रतीक रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में परंपरागत रोजगारों को या आजीविका के साधनों को आगे बढ़ाने की दिशा में कोई काम नहीं किया गया। वस्तुतः उस समय इस प्रकार के परंपरागत रोजगारों को समाप्त करने की दिशा में काम किया जा रहा था। जिससे कुंभकार, बद्धई, लोहार आदि कामगारों का काम छिनता जा रहा था। उनके कामों को बड़ी-बड़ी कंपनियां छीनती चली जा रही थीं। सरकार इस प्रकार की रोजगार छीनने वाली नीतियों को अपना संरक्षण प्रदान कर रही थी। जिससे देश में भुखमरी, गरीबी, फटेहाली बढ़ती जा रही थी। प्रधानमंत्री ने इस प्रकार बढ़ती हुई भुखमरी, फटेहाली और गरीबी पर अंकुश लगाने के लिए लोगों के परंपरागत रोजगार उन्हें सरकारी नीतियों का लाभ दिलाते हुए दिलाने शुरू किये। जिन क्षेत्रों पर चाइनीज वस्तुओं ने अपना एकाधिकार बना लिया था, देश के लोगों ने उनका मातृ खरीदना बंद कर दिया है और अपने देश के परंपरागत कामगारों द्वारा बनाई जा रही चीजों को बड़ी शान के साथ खरीद रहे हैं। दीपावली के त्यौहार को ही लें। अब हम चीनी दीपक न लेकर अपने कुंभकार भाइयों द्वारा बनाए जा रहे दीपकों को लेने में रुचि दिखाने लगे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विश्वकर्मा साथियों के लिए विश्वकर्मा योजना लागू की। 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किया गया। जिससे गरीब लोगों को सरकारी अस्पतालों में जाकर अपना उपचार करवाने में सुविधा प्राप्त हुई है। यह बात और भी अधिक अच्छी है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ऐसे कार्ड जारी करने से पहले किसी का मजबूत नहीं पूछा। 11 करोड़ परिवारों को पीने का शुद्ध पानी नलों से दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की सुविधा प्रदान की गई है। जिससे देश में लोगों ने राहत की सांस ली है। अनेक परिवारों की यह चिन्ता समाप्त हो गई है कि शाम को रसोई में कुछ बनेगा या नहीं। अनेक रेहड़ी पटरी वाले लोगों को भी सरकारी लोन अब मिल सकता है। जिससे वह अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई साधन तैयार कर पा रहे हैं। सकारात्मक परिणाम देने वाली इन नीतियों के चलते प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाने में सफलता प्राप्त हुई।

नीतियों में आलोचना की कोई गुजाइश हो सकती है पर उनका दृष्टिकोण निश्चित रूप से राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ है जनकल्याण करना ही लोकतंत्र में राजनीति और शासन का उद्देश्य होता है। इसी को प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रनीति के नाम से पुकारते हैं। वास्तव में देश के लिए राजनीति की ओच्छी चालों की बजाय राष्ट्रहित को दृष्टिपात रखकर काम करने वाली शुद्ध, विशुद्ध, परिशुद्ध राष्ट्रनीति की ही आवश्यकता है।

# भारत का सकल घरेलू उत्पाद 50 वर्षों में 52 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो जाने की संभावना

प्रह्लाद सबनानी

गोल्डमेन सेंच्स नामक अंतर्राष्ट्रीय निवेश संस्थान अपने एक रिसर्च पेपर में बताया है कि आगे आने वाले 50 वर्षों में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 52 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा। इस प्रकार भारत इस संदर्भ में अमेरिका को भी पीछे छोड़ने हुए विश्व प्रथम स्थान पर आ जाएगा। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक आदि विभिन्न वित्तीय संस्थानों ने भी आगे आने वाले समय में भारत की आर्थिक वृद्धि दर की 7.2 प्रतिशत रहने की प्रबल संभावनाएं जताईं हैं। जबकि, आज विश्व के कई देश, विशेष रूप से ब्रिटेन जर्मनी आदि, आर्थिक संकुचन के दौर से गुजर रहे हैं और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कई विकसित देश तो ऊज़ की कमी के संकट से जूझ रहे हैं। भारत के विदेशमंत्री उच्चाल पाण्डित ने यहाँ से संपादित एक ऐसी



दे सकती है क्योंकि चीन+1 की नीति का अनुपालन विश्व के कई विकसित देश आज करने लगे हैं एवं ये देश भारत में विनिर्माण के क्षेत्र में अपनी इकाईयों को स्थापित करते जा रहे हैं। ताइवान आदि देशों पर चीन की नीति की पूरे विश्व में भर्तव्य हो रही है। चीन के अपने बॉर्डर पर लगने वाले लगभग समस्त देशों के साथ चीन के सम्बंध अच्छे नहीं हैं। इन देशों का चीन पर अब भरोसा समाप्त सा होता जा रहा है। ऐपल एवं टेस्ला जैसी कम्पनियां अब भारत में अपनी विनिर्माण इकाईयां स्थापित कर रही हैं। ऐपल ने तो अपने आईफोन-15 का उत्पादन भारत में चालू भी कर दिया है। इससे भारत में न केवल रोजगार के लाभों नए अवसर निर्मित हो रहे हैं बल्कि विदेशी निवेश भी बढ़ रहा है। आज भारत में विदेशी मुद्रा भंडार 65,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास रिकार्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। साथ ही, आज भारत का पूंजी बाजार (स्टॉक मार्केट) विश्व में जौशै म्हण्या पर आ गया है।

(स्टाक मार्केट) विश्व में चाहे स्थान पर आ गया है। भारत द्वारा अपने बुनियादी ढांचे को विकसित करने में भारी भरकम राशि खर्च की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11.11 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का बजट बुनियादी ढांचे के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस मद पर खर्च की गई थी। अयोध्या, वाराणसी, उज्जैन, हरिद्वार, जम्मू कश्मीर जैसे अन्य कई धार्मिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है ताकि धार्मिक पर्यटन को भारत में बढ़ावा दिया जा सके। इन शहरों के बुनियादी ढांचे का अनुलनीय विकास किया जा रहा है। जिससे रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित हो रहे हैं। एयरपोर्ट की संख्या पिछले 10 वर्षों में दुगने से भी अधिक होकर 150 तक पहुंच गई है और इसे वर्ष 2025 तक 200 की संख्या तक ले जाया जा रहा है। रेलवे का विद्युतीकरण किया गया है। रेलगाड़ियों की स्पीड बढ़ाई गई है, जिससे देश में कार्यक्षमता के स्तर में सुधार हो रहा है। भारत के बड़े शहरों में मेट्रो रेल का जाल बिछाया जा रहा है। आज भारत का रोड नेटवर्क चीन से भी अधिक होकर विश्व में केवल अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। भारत सरकार की वर्ष 2024 से वर्ष 2030 के बीच देश के बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर 2 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि खर्च करने की योजना है। इस प्रकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2027 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसी सम्भावना भी व्यक्त की जा रही है।

डिक्टर एस जयशक्ति भारत के प्रबन्धनमत्रा नरद्र मात्रा के नेतृत्व में विश्व के लगभग समस्त सशक्त देशों के साथ अच्छे सम्बंध बनाने में सफल रहे हैं। आज रूस को भी भारत की आवश्यकता है तो अमेरिका को भी रूस, भारत को कच्चे तेल एवं सुरक्षा के लिए भारत मात्रा में शस्त्र उपलब्ध कराता है। वर्ष 2022 में भारत ने रूस से 4,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का सामान आयात किया था। वर्ष 2023 में यह बढ़कर 5,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर होने की प्रबल सम्भावना है। वहाँ अमेरिका, भारत को अपना स्ट्रेटेजिक सहयोगी मानता है। आज विश्व की समस्त बड़ी शक्तियां भारत के साथ सौहार्द पूर्ण सम्बंध चाहती हैं। रूस, अमेरिका, यूरोपीयन देश एवं अरब देश भारत के साथ अपने व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं। रूस भी भारत के साथ अच्छे सम्बंध चाहता है तो यूक्रेन भी। उधर इजराईल भी भारत के साथ अच्छे सम्बंध चाहता है तो इरान भी। भारत जी-20 समूह का सदस्य है तो भारत यूआई एवं ब्रिक्स का भी सदस्य है। इस प्रकार कुमिलाकर भारत का ढंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। आज भारत के पास विश्व की चौथी सबसे बड़ी फैल है। पश्चिमी बॉर्डर पर चीन से युद्ध की स्थिति में भारत आज इससे निपटने को पूर्णतः तैयार है।

जनसंख्या अब धीमे धीमे कम हो रही है। इन देशों में आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए आज युवाओं की सख्त आवश्यकता है जो पूरे विश्व में केवल भारत ही उपलब्ध करा सकता है। वर्ष 2064 तक भारत की जनसंख्या बढ़ती रहेगी, ऐसी सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इस प्रकार वैश्विक स्तर पर भारत विश्व में विकास के इंजन के रूप में अपनी भूमिका लग्भू समय तक निभाता रहेगा।

उक्त संदर्भ में दूसरा सबसे बड़ा कारण बताया गया है, भारत में हाल ही के समय में किया गया डिजिटलीकरण। इससे देश के ग्रामीण इलाकों में भी नागरिकों की दक्षता एवं उत्पादकता बढ़ गई है। भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की वित्तीय एवं बैंकिंग संस्थानों द्वारा भरपूर आर्थिक सहायता की जा रही है। इससे यह उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं एवं देश में रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित कर रहे हैं। पूर्व में केवल बड़े उद्योगों को ही बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती रही है परंतु भारत में अब यह ट्रैड बदला है। कार्विड महामारी के बाद से तो इस सम्बंध में बड़ा बदलाव देखने में आया है। डिजिटलीकरण के कारण छोटे छोटे व्यवसाइयों की क्रेडिट हिस्ट्री निर्मित हो रही है जिसके कारण बैंकों को इन छोटे छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में आसानी हो रही है। ‘आधार’ ने तो देश के समस्त नागरिकों की प्रकृत अल्पाधिकार दी बना दी है।

दरा बाज़ के राष्ट्रीय आवायों अधिकार परमांत्र वाले लगे हैं। यह स्थिति भारत के आर्थिक विकास को ग







# बरमकेला पुलिस की अवैध शराब बड़ी कार्यवाही, तरकर भेजा गया जेल

**बरमकेला (समय दर्शन)** | पुलिस अधीक्षक पुक्कर शर्मा के द्वारा जिले में जुआ, सद्दा, अवैध शराब, गांजा बिक्री करने वाले के विरुद्ध लगातार कार्यवाही करने हेतु निर्देश करते आ रहे हैं वे अवैध पुलिस अधीक्षक महोदय एवं उप पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुनि विजय गोपाल के निर्देशन पर आज

दिनांक 15 अप्रैल को हमराह स्टाफ प्रधन आर.विजय यादव आर.दिनेश चौहान मोहन पटेल के साथ नवरात्री के पांच दिन पर यात्रा पेट्रोलिंग के दौरान मुख्यार्थी से सुनामा मिला की ग्राम डभरा से बरमकेला की ओर बिक्री नंबर प्लेट मेहरून कलर की स्कूटी के सामने पैर दान के पास बोरी रखे एक व्यक्ति आते दिखा जिसे कंचनपुर बौक के पास रोक कर



नाम पता पूछने पर अपना नाम राकेश कुमार सिद्धार पिता

स्व.चूनीलाल सिद्धार उम्र 23 वर्ष सा.डभरा थाना बरमकेला का निवासी बतया स्कूटी में रखे बोरी के बारे में पूछने पर उसके अंदर में रखे कच्ची महुआ शराब 15-15 लिटर का 3 पत्री तथा गाड़ी के डिक्कों के तलाशी लेने पर एक पत्ती में 15 लिटर कच्ची महुआ शराब भरा मिला कुल 60 लिटर कच्ची महुआ शराब मिला जो की मौके पर किसी प्रकार का वैध कागजात नहीं किया गया, आरोपी राकेश सिद्धार के कबजे से जस (1) 60 लिटर कच्ची महुआ शराब कीमती 12000 रु (2) एक स्कूटी कीमती 40000 रु (3)एक ओपो बोबाइल कीमती 5000 रु को जस कर धारा 34(2)59(क) आबकारी एकट के तहत गिरफ्तार कर 15 अप्रैल को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

## विश्व हिन्दू परिषद का जिला स्तरीय बैठक सम्पन्न



## श्रीकृष्ण की अष्ट धातु से मूर्ति निर्माण को लेकर ठेटवार यादव समाज में है उत्साह

**समाज के प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय, रायपुर में जुटे समाज के लोग**

**रायपुर (समय दर्शन)** | प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ की बैठक रायपुर राज मुख्यालय ठेटवार भवन रायपुर में सह संयोजिका, अभ्यु धूतहार जिला प्रचार प्रसार प्रमुख, चंद्रभान साह अग्रवाल व बस्तत वेवता के नेतृत्व में जिला स्तरीय बैठक सम्पन्न हुआ।

रविवार को आयोजित विश्व हिन्दू परिषद की बैठक में अनुयानिक संगठन के स्वयं संवेदकों के साथ बजाये दल, मारु शक्ति, दुर्गा बाहनी, गौ सेवक बंधु भगिनी बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए।

बैठक में ऊर्जवान कार्यकर्ताओं को शक्ति, धूमधारी व अन्य वाहनों के प्रवर्षण के द्वारा जिला स्तरीय बैठक सम्पन्न हुआ।

प्रदेश महासचिव नरोत्तम यदु ने बैठक के उद्देश्य के अध्यात्म से श्री कृष्ण की मूर्ति निर्माण हेतु प्रस्ताव पारित किया गया।

महासभा के बैठक का अध्यक्ष श्री योगेश यदु, बैठक की संयुक्त बैठक अध्योजित कर संवालन समिति गठित करने के लोगों ने क्रमशः अपने अपने विचार रखे। रामसिंह यादव, परमानंद यादव संतोष यदु, बस्तत यदु विमल प्रकाश यदु हरिराम यदु, भोजराम अहर, भगत, एवं सामाजिक जनों ने अपना - अपना विचार रखे। नागर यदु प्रदेश उपाध्यक्ष के खाते में राशि जमा करने प्रस्ताव पारित किया गया।

यदु विमल प्रकाश यदु विचार अधिकारियों से अपने वाट के बारे में जिला स्तरीय बैठक 19 मई दिन रविवार को



प्रतिवाहिक बनाने श्री कृष्ण भगवान की अष्टधातु से मूर्ति निर्माण कर स्थापना करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। महासभा सुख्ख कार्यकर्ता, महालल प्रकोष्ठ युवा प्रकाश की संयुक्त बैठक अध्योजित कर संवालन समिति गठित करने का नियमण: अपने अपने विचार रखे। रामसिंह यादव, परमानंद यादव संतोष यदु, बस्तत यदु विमल प्रकाश यदु हरिराम यदु, भोजराम अहर, भगत, एवं सामाजिक जनों ने अपना - अपना विचार रखे। नागर यदु प्रदेश उपाध्यक्ष के खाते में राशि जमा करने प्रस्ताव पारित किया गया।

यदु विमल प्रकाश यदु विचार अधिकारियों से अपने वाट के बारे में जिला स्तरीय बैठक 19 मई दिन रविवार को

प्रस्ताव पारित किये। जिसमें निम्न प्रस्ताव पारित किया गया।

यादव ठेटवार समाज महासभा का शताब्दी वर्ष 2026 में पूर्ण होने जा रहा है। शताब्दी वर्ष को

प्रवास समिति बनाया जायेगा।

अष्टधातु संग्रहण पूर्व बैठक में लिए प्रस्ताव अनुसार चैत्र नवात्र पर 09 अप्रैल 2024 से प्रांतीय किया जा चुका है। अंतिम तिथि 15 जून 2024 तक राज पार जिला इकाईयों द्वारा धातु संग्रहित होने के बाद यादव धार्यों द्वारा प्रकोष्ठ युवा प्रकाश की धातु संग्रहण करने की अंतिम तिथि 07 जुलाई 2024 रथयात्रा को निर्धारित किया गया है। आगामी विचार 19 मई दिन रविवार को समर्पण राशि एकत्रित करने के सभी सदस्यों से अष्ट धातु दान लेने का निर्णय लिया गया। अष्ट धातु मूर्ति निर्माण हेतु योग्य युवा प्रकाश के खाते में राशि जमा करने प्रस्ताव पारित किया गया। अष्ट धातु संग्रहण करने के सभी सदस्यों से अष्ट धातु दान लेने का निर्णय लिया गया। यदु विमल प्रकाश यदु विचार अधिकारियों के बारे में जिला स्तरीय बैठक 19 मई दिन रविवार को

प्रस्ताव पारित किया गया।

यादव ठेटवार समाज महासभा का शताब्दी वर्ष 2026 में जिला स्तरीय बैठक 19 मई दिन रविवार को

प्रस्ताव पारित किया गया।

यादव ठेटवार समाज महासभा का शताब्दी वर्ष 2026 में जिला स्तरीय बैठक 19 मई दिन रविवार को

प्रस्ताव पारित किया गया।

यादव ठेटवार समाज महासभा का शताब्दी वर्ष 2026 में जिला स्तरीय बैठक 19 मई दिन रविवार को

प्रस्ताव पारित किया गया।

यादव ठेटवार समाज महासभा का शताब्दी वर्ष 2026 में जिला स्तरीय बैठक 19 मई दिन रविवार को

प्रस्ताव पारित किया गया।

यादव ठेटवार समाज महासभा का शताब्दी वर्ष 2026 में जिला स्तरीय बैठक 19 मई दिन रविवार को

प्रस्ताव पारित किया गया।

यादव ठेटवार समाज महासभा का शताब्दी वर्ष 2026 में जिला स्तरीय बैठक 19 मई दिन रविवार को

प्रस्ताव पारित किया गया।

यादव ठेटवार समाज महासभा का शताब्दी वर्ष 2026 में जिला स्तरीय बैठक 19 मई दिन रविवार को

प्रस्ताव पारित किया गया।

यादव ठेटवार समाज महासभा का शताब्दी वर्ष 2026 में जिला स्तरीय बैठक 19 मई दिन रविवार को

प्रस्ताव पारित किया गया।

यादव ठेटवार समाज महासभा का शताब्दी वर्ष 2026 में जिला स्तरीय बैठक 19 मई दिन रविवार को

प्रस्ताव पारित किया गया।

यादव ठेटवार समाज महासभा का शताब्दी वर्ष 2026 में जिला स्तरीय बैठक 19 मई दिन रविवार को

प्रस्ताव पारित किया गया।

यादव ठेटवार समाज महासभा का शताब्दी वर्ष 2026 में जिला स्तरीय बैठक 19 मई दिन रविवार को

प्रस्ताव पारित किया गया।

यादव ठेटवार समाज महासभा का शताब्दी वर्ष 2026 में जिला स्तरीय बैठक 19 मई दिन रविवार को

प्रस्ताव पारित किया गया।

यादव ठेटवार समाज महासभा का शताब्दी वर्ष 2026 में जिला स्तरीय बैठक 19 मई दिन रविवार को

प्रस्ताव पारित किया गया।

यादव ठेटवार समाज महासभा का शताब्दी वर्ष 2026 में जिला स्तरीय बैठक 19 मई दिन रविवार को

प्रस्ताव पारित किया गया।

यादव ठेटवार समाज महासभा का शताब्दी वर्ष 2026 में जिला स्तरीय बैठक 19 मई दिन रविवार को

प्रस्ताव पारित किया गया।

यादव ठेटवार समाज महासभा का शताब्दी वर्ष 2026 में जिला स्तरीय बैठक 19 मई दिन रविवार को

प्रस्ताव पारित किया गया।

यादव ठेटवार समाज महासभा का शताब्दी वर्ष 2026 में जिला स्तरीय बैठक 19 मई दिन रविवार को

प्रस्ताव पारित किया गया।

यादव ठेटवार समाज महासभा का शताब्दी वर्ष 2026 में जिला स्तरीय बैठक 19 मई दिन रविवार को

प्रस्ताव पारित किया गया।

यादव ठेटवार समाज मह